

વિચાર

भाजपा की कामयाबी से बढ़ी कांग्रेस की मुश्किलें

राजस्थान के सात विधानसभा उपचुनाव के परिणामों ने छोटे राजनीतिक दलों और विपक्षी कांग्रेस को करारी हार दी है। इस हार ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भविष्य को अनिश्चितता की ओर मोड़ दिया। इस वर्ष के प्रारम्भ में भाजपा, दो विधानसभा उपचुनावों में हार चुकी थी। साफ है जून में कांग्रेस, जो गठबंधन को लोकसभा की 25 में से 11 सीटें दे चुकी थी, ने 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर संगठनात्मक मजबूती हासिल की। यह अप्रत्याशित जीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार को संकट से उबारने में सफल रही। इन सात विधानसभा सीटों में से भाजपा ने पांच सीटें — झुंझुनू, रामगढ़, देवली-उनियारा, खींवसर और सलूंबर — जीतीं, जबकि भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने चौरासी सीट और कांग्रेस ने दौसा सीट पर विजय प्राप्त की। इस बार के चुनाव परिणामों का निष्कर्ष है कि मतदाताओं ने परिवारवाद और सहानुभूति की राजनीति को नकार दिया। कांग्रेस ने रामगढ़ सीट पर स्व. जुबेरखान के बेटे, आर्यन जुबैर को सहानुभूति आधारित जीत के लिए खड़ा किया था, जबकि इस सीट पर स्व. जुबैर चार बार और एक बार उनकी पत्नी साफिया कांग्रेस की विधायक रह चुकी थीं। बावजूद इसके, भाजपा के सुखवंत सिंह ने आर्यन को भारी शिकस्त दी। झुंझुनू विधानसभा सीट, जो ओला परिवार के नाम से प्रसिद्ध है, से जाट नेता स्व. शीशराम ओला ने 8 बार विधानसभा और 5 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। इस बार उनके पुत्र बृजेंद्र ओला, जो जून में सांसद चुने गए थे, अपने पुत्र अमित ओला को विजय दिलाने में असफल रहे। भाजपा के राजेंद्र भांबू ने भारी मतों (42,848) से जीत हासिल की। सहानुभूति लहर का फायदा भाजपा ने सलूंबर सीट पर उठाया, जहां स्व. अमतलाल मीणा की पत्नी, शांता देवी मीणा (जो तीन बार सरपंच रह चुकी हैं), अंतिम राउंड की गिनती में 1285 वोट से जीत गई। बीएपी के प्रत्याशी जीतेश कटारा ने चुनाव आयोग से भाजपा सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत की थी। बीएपी प्रमुख और डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने भी चुनाव आयोग को शिकायत की कि उनकी पार्टी सलूंबर सीट पर एकतरफा जीत रही थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए जल्दी-जल्दी मतगणना करा कर अपने प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दिलवा दिया। आरएलपी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि पार्टी प्रमुख और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को खींवसर विधानसभा सीट पर नहीं जिता सके। उनकी पार्टी राजस्थान विधानसभा में भी शून्य पर रही।

उदास लोगों का देश बनना भारत की एक ग्रासदी

लिलित गर्ग

भारत उदास, निराश एवं थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। हम प्रसन्न समाजों की सूची में अब्बल नहीं आ पा रहे हैं। आज अक्सर लोग थके हुए, उदास, निराश नजर आते हैं, बहुत से लोग हैं जो रोज़मर्ग के काम करने में ही थक जाते हैं। उनका कुछ करने का ही मन नहीं होता। छोटे-मोटे काम भी थकाऊ और उबाऊ लगते हैं। विडम्बना तो यह है कि लम्बे विश्राम एवं लम्बी छुट्टियों के बाद भी हम खुद को तरोताजा नहीं बना पा रहे हैं। भारत में ऐसे लोगों का प्रतिशत लगभग 48 तक पहुंच गया है, जो चिन्ता का बड़ा सबब है। ऐसे थके एवं निराश लोगों के बल पर हम कैसे विकसित भारत एवं नये भारत का सपना साकार कर पायेंगे? यह सवाल सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन करने का अवसर दे रहा है, वहीं नीति-निर्माताओं को भी सोचना होगा कि कहाँ समाज निर्माण में त्रुटि हो रही है कि हम लगातार थके हुए लोगों के देश के रूप में पहचाने जा रहे हैं। खुशहाल देशों की सूची में भी हम सम्मानजनक

कारण हो सकते हैं—जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होना, कृषि पर ज्यादा निर्भरता, आर्थिक विकास की दर कम होना, बेरोज़गारी, अशिक्षा, आय में असमानता, भूष्टाचार, आतंरिक द्रेष, कमज़ोर आर्थिक नीतियाँ एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया। दुःख जीवन के उत्तर-चाहाव का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह इंसान खुशी, निराशा, उडासी, गुस्सा, गर्व आदि भावनाओं को महसूस करता है, उसी तरह हर कोई समय-समय पर दुःख महसूस करता है। दुःख कभी-कभी इंसान को मोटीवेट करने में भी मदद कर सकता है, लैकिन यह जिरीविषा, खुशहाली, सक्रियता, जोश को भी कम करता है। दुनिया की खुशहाल देशों की सूची में भारत इस वर्ष 143 देशों में 126वें स्थान पर है। यह ऐक पिछले साल के मुकाबले बिल्कुल वही रही है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन 60वें, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है।

भारत दुनिया का सबसे उदास देश है। शोधों के निष्कर्ष बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन एवं अत्यधिक गर्मी के कारण 2100 तक भारत में हर साल 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है? इसी कारण उदास लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। 2018 की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सबसे अधिक अवसादग्रस्त देशों की सूची में सबसे ऊपर है। भले ही भारतीयों को स्वभाव से समायोजित और संतुष्ट लोगों के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह पता चला है कि वे सबसे अधिक उदास भी हैं। एक तरफ हम खुद को किसी भी चीज़ में आसानी से समायोजित कर लेते हैं, चाहे वह कम पैसा हो, खराब सड़कें हों, बुनियादी ढाँचे की कमी हो या कछ भी हों। नेशनल केयर ऑफ मेडिकल हेल्थ के



एक अध्ययन के अनुसार लगभग 6.5 प्रतिशत भारतीय गंभीर मानसिक स्थितियों से पीड़ित हैं, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी। सरकार जागरूकता कार्यक्रम चला रही है लेकिन मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टरों की भी कमी है।

भारत के मानव-स्वभाव में उग्र हो रही उदासी एवं निराशा का बड़ा कारण प्रदूषित हवा एवं पर्यावरण है। शुद्ध वायु में ही जीवन है और उसी में जीवन की सकारात्मकता एवं जीवन-ऊर्जा समाहित है। यही हमारी अराजक जीवन शैली को संयमित कर सकती है। कछु ऐसे रोग जो उपचार

जलवायु परिवर्तन के खतरों से बच्यों को बचाएँ

ललित गर्ज

हाल ही में प्रस्तृत हुई यूनिसेफ की रिपोर्ट 'द यूचर ऑफ चिल्ड्रेन इन चॉइंग वर्ल्ड' ने भारत में बच्चों के भविष्य को लेकर उत्पन्न चुनौतियों, ग्रासद स्थितियों एवं भयावह भविष्य को जागर किया है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि साल 2050 तक भारत में 35 करोड़ बच्चे जनसांख्यिकीय बदलावों, जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमांश और तकनीकी बदलावों की चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। उस समय जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के बाद जीवन में जलवायु परिवर्तन के संकटों से जुझना होगा, भीषण लू, गरमी, बाढ़, तूफान, घऋगवात और अनेक जलवायु जनित बीमारियों से सामना करना होगा। वायु प्रदूषण की विभीषिका, गहराते जल संकट, सिमटते प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन व रोजगार की विसंगतियों के बीच आने वाली पीढ़ी के बच्चों का जीवन निसंदेह संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण एवं संकटपूर्ण होगा।

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)



वर्ष 2021 में बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कुल 163 देशों की सूची में 26वें स्थान पर था। ऐसे में भारत में बच्चों को अधिक गर्मी, बाढ़ और वायु प्रदूषण से गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों में यह संभ्या ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2050 में बच्चों को 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना गर्मी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर है, जलवायु संकट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा तथा पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। चिंता की बात यह है कि इन तमाम विसंगतियों, विषमताओं व नेतृत्व की अदूरदरिशता के बीच बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरों के लिये संवेदनशीलता के साथ सावधान एवं सतर्क दौरे पर्व उचित-प्रभावी कार्ययोजना बनाने की ज़रूरत है।

हान एवं उच्चत-प्रभावा काययाजना बनान का जरूरत ह। इसी तरह, गहरे डिजिटल विभाजन के बीच एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों के लिए अच्छी और बुरी, दोनों हो सकती है। एक ताज आंकड़ा बताता है कि उच्च आय वाले देशों में 95 फीसदी आबादी इंटरनेट से जुड़ी है, तो निम्न आय वाले देशों में सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। भारत में वर्तमान में इंटरनेट की व्यापकता ने बच्चों के जीवन में अनेक सकट खड़े किये हैं। यूनिसेफ ने इस डिजिटल डिवाइड को पाटने और बच्चों तक नयी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षित एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी पहल की वकालत की है। बच्चे चंकि हमारा भविष्य हैं, इसलिए बच्चों और उनके अधिकारों

प्रतिशत से अधिक उत्पन्न करते हैं और उन्हें तेजी से विकास हासिल करने के लिए इंजन माना जाता है। वे विकास और नवाचार, विविधता और कनेक्टिविटी के दुनिया के सबसे मजबूत स्रोतों में से हैं और संभावित रूप से बच्चों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं।

बढ़ता शहरीकरण बड़ी असमानताओं को भी जन्म दे सकते हैं। आज शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 4 बिलियन लोगों में से लगभग एक तिहाई बच्चे हैं। यह अनुमान है कि 2050 तक, दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, जिनमें से कई द्युग्मी-झोपड़ियों में रहेंगे। इसलिये शहर स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकते हैं, भीड़भाड़ और उच्च प्रवेश लागत के कारण सबसे गरीब शहरी बच्चे उन तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। अन्य चुनौतियाँ जो शहरी गरीबों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से द्युग्मी-झोपड़ियों में रहने वालों को, उनमें भीड़भाड़ और अपर्याप्त सफाई व्यवस्थाएं शामिल हैं—जो बीमारियों के फैलने में सहायक होती हैं—किफायती और सुरक्षित आवास की कमी, परिवहन की खराब पहुंच और बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि आदि हैं। उल्लेखनीय है कि उस समय देश जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौती से जूझ रहा होगा। आकलन किया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते ही वर्तमान की तुलना में बच्चों की संख्या में करीब दस करोड़ की कमी आएगी। वर्तमान में पूरी दुनिया में एक अरब बच्चे उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों का मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर सरकारें अभी से नहीं चेती तो 2050 की स्थिति का सहज आकलन किया जा सकता है। मासूम चेहरों एवं चमकती आंखों का नया बचपन भारत के भाल पर उजागर एवं कायम करने के लिये सरकारों को गंभीर होना होगा। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आधुनिक मानवतावाद और पूँजीवाद से प्रभावित होकर प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे परिवारों और बाल देखभाल प्रदाताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। वर्तमान में मौजूद रहने के बजाय, लोग भविष्य के बारे में सोचने में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। और ज्यादातर मामलों में वे इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि व्यापक अर्थों में सफल जीवन कैसा हो सकता है, बल्कि इसके बजाय वे स्कूल और कार्यस्थल में सफलता के बारे में सोच रहे हैं। यह कुछ कौशलों पर बहुत अधिक जोर देता है, जबकि अन्य—जैसे रचनात्मकता, सामाजिक क्षमता, जीवनमूल्य और उत्साह—को कम महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे अधिक उन्नत शैक्षणिक ट्रैक या अधिक प्रतिष्ठित करियर में चयन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में कई प्रतिशत अविकसित रह जाती हैं। अगर समाज को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है—चाहे वह भविष्य आखिरकार कैसा भी क्यों न हो, तो भविष्य के खतरों की आट को सुनते हुए जागरूक होना होगा। साफ है, नीति के स्तर पर प्रदूषण एवं बदलते मौसम की मार के लिये काम करना होगा। कम से कम भविष्य या बच्चों के लिये तो ऐसा किया ही जाना चाहिए। निश्चित ही यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट बच्चों के भविष्य की चिंताओं पर मंथन करने तथा उसके अनुरूप नीति-नियंत्रणों से नीतियां बनाने का सबल आग्रह करती है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में डिजिटल विभाजन भी एक बड़ी चुनौती होगी। तब तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग चरम पर होगा। जाहिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहां तक का मुख्य साधन होगी, वहीं इसकी विसंगतियों का प्रभाव रोजगार के अवसरों एवं सामाजिक-परिवारिक संरचना पर भी पड़ेगा। जहां दुनिया के विकसित देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट से जुड़ने के कारण प्रगति की राह में सरपट दौड़ रही है, तो गरीब मुल्कों में यह प्रतिशत विकसित देशों के मुकाबले करीब एक चौथाई ही है। ऐसे में समतामूलक आदर्श समाज की स्थापना के लिये डिजिटल डिवाइड को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके मद्देनजर हमारी कोशिश हो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप समावेशी हो। ताकि आधुनिक तकनीक तक बच्चों की समान व सुरक्षित पहुंच हो सके। निर्विवाद रूप से बच्चे आने वाले कल के लिये देश का भविष्य निर्धारक होते हैं। ऐसे में हर लोक कल्याणकारी सरकार का नैतिक दायित्व है कि अपनी रीतियों—नीतियों में बच्चों के हितों व अधिकारों को प्राथमिकता दे। तभी हम उनके सखद भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।

से भिरा है, कॉरपोरेट संस्कृति में रिश्ते, स्वास्थ्य एवं खुशहाली बहुत पीछे छूट रही है। वास्तव में अधिकांश आधुनिक रोग काम न करने की बीमारी है। हम लोग दिमाग को थका रहे हैं, शरीर को नहीं थका रहे हैं। इसी बजह से शरीर को? भुगताना पड़ रहा है। आदमी पैदल नहीं चल रहा है। स्वस्थ रहने के लिये जरूरी है हम आहार सही ढंग से लें। दरअसल हमारा आहार दवा है। देर रात भोजन करना, देर रात तक जगना एवं सुबह देर से उठना शरीर के साथ अत्याचार करने जैसा है। इन्हीं जटिल से जटिलतर होती स्थितियों ने हमें उदासी दी है। वैसे उदासी, निराशा, थकावट, दुख या खुशी एक ऐसी अवस्था है, जिस पर किसी सर्वे के जरिये एकमत नहीं हुआ जा सकता। फिर भी, ऐसी सूचियों से सकारात्मक प्रेरणा लेते हुए प्रसन्न, उत्साही, सक्रिय समाज की संरचना के लिये तमाम तरह के प्रयास करने में ही भलाई है।

तरह के प्रयास करने म हा भलाइ ह।
हमारा शीर्ष नेतृत्व आजादी के बाद से ही
निरन्तर आदर्शवाद और अच्छाई का झूठ रखते हुए
सच्चे आदर्शवाद के प्रकट होने की असंभव कामना
करता रहा है, इसी से जीवन की समस्याएं सघन
होती गयी है, इसी ने उदासी को बढ़ाया है,
नकारात्मकता का व्यूह मजबूत होता गया है, खुशी,
उत्साही, जाशीला एवं प्रसन्न जीवन का लक्ष्य अधूरा
ही रहा है, इनसे बाहर निकलना असंभव-सा होता
जा रहा है। दूषित और दमघोंट वातावरण में आदमी
अपने आपको टूटा-टूटा सा अनुभव कर रहा है।
आर्थिक असतुलन, बढ़ती महगाई, बेरोजगारी,
बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार उसकी
धमनियों में कुत्सित विचारों का रक्त संचरित कर
रहा है। ऐसे जटिल हालातों में इंसान कैसे खुशहाल,
जोशीला एवं सकारात्मक जीवन जी सकता है?

